भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3862**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पण्यवस्तु के व्यापार संबंधी घाटे में वृद्धि

3862 डॉ.राज कुमार चब्बेवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन नवीनतम रिपोर्टों की जानकारी है जो दर्शाती हैं कि भारत का वस्तु व्यापार संबंधी घाटा बढ़कर पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वर्ण, उर्वरकों और अन्य पण्यवस्तु के उच्च आयात के योगदान सहित व्यापार घाटे में इस तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है;
(ग) क्या यह सही है कि आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन पर सरकार की नीतियां वांछित परिणाम नहीं दे पाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(घ) क्या सरकार ने बढ़ते व्यापार घाटे के चालू खाता शेष, रुपये के मूल्य, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार और समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता पर संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) रणनीतिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने सहित व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार पण्यवस्तु के व्यापार संबंधी घाटे सहित व्यापार कार्य-निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखती है। पण्यवस्तु के व्यापार की प्रकृति मौसमी होने के कारण किसी एक माह में हुआ घाटा अपने आप में समग्र व्यापार कार्य-निष्पादन को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जून 2026 में 30.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पण्यवस्तु व्यापार घाटा, जिसे पांच महीनों का उच्च स्तर बताया गया वह 12 महीने के औसत घाटे 29.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नाममात्र रूप से उच्च था,जो यह दर्शाता है कि जून 2026 का घाटा मोटे तौर पर औसत स्तर के अनुरूप रहा। इसके अलावा,वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के दौरान पण्यवस्तु निर्यात तिमाही में अब तक का उच्चतम 129.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है,जबकि पिछले वर्ष इस

अवधि के दौरान यह 111.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था,जो 16.1% की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है और यह व्यापार संबंधी घाटे में मासिक उतार-चढ़ाव होने के बावजूद भारत के निर्यात कार्य-निष्पादन की अंतर्निहित मजबूती को रेखांकित करता है।

(ख) पण्यवस्तु व्यापार घाटा मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की आयात संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। भारत के आयात के एक महत्वपूर्ण शेयर में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक सामान,मशीनरी और पूंजीगत सामान,स्वर्ण एवं कीमती पत्थर,उर्वरक और अन्य इंटरमिडिएट इनपुट्स शामिल है, जो घरेलू खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, विनिर्माण,अवसंरचना विकास और औद्योगिक विस्तार को सहायता प्रदान के लिए आवश्यक हैं। आयात में सबसे बड़ा योगदान पेट्रोलियम उत्पादों (एचएस 27) का है,जो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल आयात का लगभग 26% रहा है और इसलिए अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का पण्यवस्तु व्यापार संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं (एचएस 84) और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं (एचएस 85) का आयात भारत के कुल आयात का लगभग एक चौथाई हिस्सा रहा है और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, डिजिटलीकरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ बढ़ते एकीकरण के अनुरूप इसमें वृद्धि हुई है। स्वर्ण,कीमती पत्थरों और रत्नों (एचएस 71) का आयात,जो कुल आयात का लगभग 14% था, ने भी आयात बिल में वृद्धि में योगदान दिया है, जबकि उर्वरकों और अन्य औद्योगिक इनपुट्स का आयात कृषि और घरेलू उत्पादन को सहायता देने के लिए आवश्यक बना रहा। तदनुसार, पण्यवस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से भारत के बाह्य क्षेत्र में किसी संरचनात्मक कमजोरी के बजाय आर्थिक विकास, औद्योगीकरण और निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक और उत्पादक पण्यवस्तु के उच्च आयात को प्रदर्शित करती है।

(ग) सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है जिसका उद्देश्य दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करना है-घरेलू क्षमता निर्माण के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करना और साथ ही संवर्धित प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार पहुंच और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ गहन एकीकरण के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना। इस उपायों ने भारत के बाह्य क्षेत्र को बहुत सुदृढ़ बनाया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद,भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया, जिसमें 441.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पण्यवस्तु और 421.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सेवा निर्यात शामिल हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-जून में भी यह वृद्धि बनी रही, जिसमें पण्यवस्तु निर्यात 129.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया,जो भारत के इतिहास में अब तक की उच्चतम त्रैमासिक कार्य-निष्पादन को दर्शाता है। यह उपलब्धि चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार परिवेश में बाह्य क्षेत्र की मजबूती और भारतीय निर्यात की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। सरकारी नीतियों ने एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासों के साथ-साथ निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाया है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है और बाह्य जोखिमों को कम किया है।

(घ) सरकार बाह्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों का निरंतर आकलन करती है जिसमें चालू खाता शेष, विनिमय दर,मुद्रास्फीति,विदेशी मुद्रा भंडार और समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता पर पण्यवस्तु व्यापार घाटे में संभावित प्रभाव शामिल हैं। हालांकि उच्च पण्यवस्तु व्यापार घाटा आयात भुगतान को बढ़ा सकता है और चालू खाते तथा विनिमय दर पर दबाव डाल सकता है लेकिन इसके प्रभाव को भारत के समग्र बाह्य क्षेत्र की मजबूती के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में और 2026-27 की पहली तिमाही में अब तक का उच्चतम तिमाही निर्यात दर्ज किया है। मजबूत सेवा व्यापार अधिशेष, प्रबल प्रेषण प्रवाह और स्थिर पूंजी प्रवाह भुगतान संतुलन को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते रहे हैं। चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 2.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.7%, वर्ष 2024-25 में 0.6% और वर्ष 2025-26 में 0.6% हो गया, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार जून 2026 में 671.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा। तदनुसार,भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता को पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है।

(ड.) व्यापार घाटे को कम करने और बाह्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना दोनों है। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमताओं में सुधार करना,निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना,बाह्य जोखिमों को कम करना और बाह्य क्षेत्र की सतत दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित करना है।

निर्यात के क्षेत्र में, सरकार प्रतिस्पर्धात्मकता,बाजार पहुंच और व्यापार सुगमता में सुधार लाने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी),2023, निर्यात प्रोत्साहन मिशन, निर्यात केंद्र के रूप जिला पहल, ट्रेड ई-कनेक्ट,ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और सीमा शुल्क आधुनिकीकरण जैसे पहलों को क्रियान्वित कर रही है। भारत ने हाल ही में हुए कई प्रमुख समझौतों सहित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से अधिमान्य बाजार पहुंच का विस्तार भी किया है।

इसके साथ ही,सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं (पीएलआई), प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीसी), आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण पहलों और प्रौद्योगिकी अपनाने एवं नवीनीकरण को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत कर रही है और रणनीतिक आयात पर निर्भरता कम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जबकि क्रूड ऑयल, उर्वरक और अन्य रणनीतिक वस्तु सहित आयात के स्रोतों में विविधता लाई जा रही है। इसके अलावा,विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों,निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संगठनों के साथ निर्यात कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी की जा रही है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

यह विभाग आयात के रुझानों की नियमित रूप से निगरानी भी करता है और संबंधित मंत्रालयों,विभागों और अन्य हितधारकों को घरेलू आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने,व्यापार संबंधी उपायों का समय पर प्रयोग करने,गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को लागू करने, उत्पत्ति नियमों को लागू करने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार सहित टैरिफ युक्तिकरण और महत्वपूर्ण आयातित वस्तुओं की निरंतर निगरानी करने जैसे उपायों के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करने के लिए जागरूक करता है।

*****